भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2588

(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन,1946 (शक) को दिया जाना है।

निवेश हेतु गंतव्य

2588. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डीः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पीडब्ल्यूसी के अनुसार देश विश्व में निवेश हेतु पांचवां सबसे आकर्षक गंतव्य बन गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पूर्व में 2020 में चौथे स्थान से 2022 में पांचवें स्थान और 2023 में नौवें स्थान पर पिछड़ने के मद्देनजर सरकार इस स्थान को किस प्रकार बनाए रखने की योजना बना रही है;

(घ) इस रैंक को और ऊपर ले जाने के लिए नीतिगत हस्तक्षेपों और प्रशासनिक उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अतिरिक्त पूंजीगत व्यय और घरेलू मांग किस हद तक सहायक है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ) जी हां, पीडब्ल्यूसी के 27वें वार्षिक वैश्विक सीईओ सर्वेक्षण के अनुसार, भारत विश्व का 5वां सर्वाधिक आकर्षक निवेश स्थल बन गया है। तथापि, निजी संस्थान, रेटिंग एजेंसियां और अन्य वैश्विक निकाय समय-समय पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपने स्वयं के आंतरिक अनुसंधान प्रकाशित करते हैं, जो विशिष्ट पूर्वानुमानों पर आधारित होते हैं, जो प्राय एक दूसरे से भिन्न होते हैं और भारत सरकार के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। सरकार ने भारत में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर कार्यक्रम, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना (ईओडीबी) और अनुपालन के बोझ को कम करना, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस), इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक, परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी), एफडीआई नीति का उदारीकरण सरकार द्वारा औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और इस प्रकार देश में निवेश बढ़ाने के लिए की गई कुछ प्रमुख पहलें हैं। सरकार ने

निवेशक-अनुकूल नीति बनाई है, जिसमें रणनीतिक रूप से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र औटोमेटिक रूट के तहत 100 %एफडीआई के लिए खुले हैं। 90% से अधिक एफडीआई अंतर्वाह ऑटोमैटिक रूट के तहत प्राप्त होता है। भारत ने एफडीआई सीमा बढ़ाकर, विनियामक बाधाओं को दूर करके, अवसंरचना का विकास करके और व्यवसायिक माहौल में सुधार करके वैश्विक निवेशकों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था के द्वार खुले रखे हैं। उदाहरण के लिए, केंद्रीय बजट 2025 में बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई की क्षेत्रीय सीमा को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100% करने की घोषणा की गई थी। सरकार हमेशा विनियामक बाधाओं को दूर करके, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, अवसंरचना का विकास करके, लॉजिस्टिक को बेहतर बनाकर और व्यापार करने में सुगमता (ईओडीबी) को बढ़ाकर व्यावसायिक वातावरण में सुधार करके अधिक एफडीआई को आकर्षित करने का प्रयास करती है।

(ङ) पूंजीगत व्यय और मजबूत घरेलू मांग किसी देश में निवेश करने के आकर्षण को काफी बढ़ाती है। अन्य बातों के अलावा, अवसंरचना व्यय व्यावसायिक लागत को कम करता है और उत्पादकता में सुधार करता है, जिससे अधिक निवेश आकर्षित करने में मदद मिलती है। इस संबंध में बजट 2025 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के 9.49 लाख करोड़ रुपये के वास्तविक की तुलना में संशोधित अनुमान 2024-25 में कुल पूंजीगत व्यय 10.18 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए कराधान संबंधी उपायों सहित कई पहलें की गई हैं, जिससे घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिला है।

*****